रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 20 मई, 1986/30 वैशाख, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

VIGILANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st April, 1986

No. VIG (A)-(9)-1/84.—*In exercise of the powers conferred upon him by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (Act No. 60 of 1952) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in continuation of this Department's notification of even number, dated the 3rd January, 1986, under which the period for the submission of the report to the State Government by the Commission of Inquiry was extended upto 31st March, 1986, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to extend the period further for the submission of aforesaid report to the State Government by the Commission of Inquiry appointed vide this Government notification of even number dated the 7th March, 1984, read with notification of even number, dated the 4th December, 1984, published in the Extraordinary issue of Rajpatra, Himachal Pradesh, dated the 7th March, 1984 and 4th December, 1984, respectively upto 30th April, 1986.*

By order,
A. K. MOHAPATRA,
Secretary.

1108-राजपत्र/86-20-5-86—1,294.

मूल्यः 20 पैसे ।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd April, 1986

No. 6-25/77-TPT.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of section 14 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exempt the Vehicle No. UHJ-9546 of Swami Dayanandji Maharaj Chitrakut Akhand Ashram from the payment of token tax in the Pradesh.

By order,
S. S. SIDHU,
Secretary.

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 अप्रैल, 1986

संख्या एल0 एस0 जी0 (1)-18/83.—नगर निगम शिमला द्वारा, हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट, 1979 (1980 का 9) की धारा 395 की उप-धारा (1) के खण्ड (एच) के साथ पठित धारा 339 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाई गई निम्नलिखित उप-विधियां जिनका हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने उक्त अधिनियम की धारा 397 के अधीन तथा अपेक्षित अनुमोदन कर दिया है, जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है और ये इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से नगर निगम शिमला के क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.—(1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम शिमला नगर निगम अस्तबल व गोशाला उप-विधि, 1985 है ।

(2) ये उप-विधियां तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

2. परिभाषाऐं.—इन उप-विधियों में जब तक कोई बात संदर्भ में विरुद्ध न हो :—

(i) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1979 अभिप्रेत है,
(ii) "गोशाला" से ऐसे स्थान जहां (भाड़े के लिये) बैल और दुधारू पशु रखे जाते हैं अभिप्रेत है,
(iii) "अस्तबल" से ऐसा स्थान जहां घोड़े, टट्टू या खच्चरें रखी जाती हैं अभिप्रेत है ।

3. परिसरों का उपयोग.—कोई भी व्यक्ति नगर निगम अनुज्ञप्ति लिए बिना किसी परिसर या उसके किसी भाग को अस्तबल या गोशाला के रूप में प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा । निगम का स्वास्थ्य अधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा ।

4. अनुज्ञप्ति के लिए शर्तें—किसी परिसर या इसके किसी भाग को अस्तबल या गोशाला के रूप में प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदन करने पर किसी भी समय अनुज्ञप्त परिसरों में की जाएगी :—

(क) अनुज्ञप्तिधारी, उसकी अनुज्ञप्ति में विहित पशुओं से अधिक पशु या उसमें विनिर्दिष्ट वर्णन से भिन्न कुछ नहीं रखेगा या रखे जाने की अनुमति नहीं देगा ।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्त परिसरों में खाना बनाने या परिसर को मानवीय निवास के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगा । परन्तु पशुओं में दुर्घटना रोकने के लिए अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिचारकों में से कतिपय परिचारकों को अनुज्ञप्त परिसरों में सोने की अनुमति दी जा सकेगी ।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी किसी सुविधाजनक स्थान पर गोबर, कूड़ा-कबरा के लिए पात्रों की व्यवस्था करेगा । इन पात्रों का आकार और सामग्री जिस से ये बने हों, ऐसी होगी जैसी कि निगम का स्वास्थ्य अधिकारी निदेशित करे । यह पात्र, प्रति पशु के लिए जो परिसर पर रखा गया है, $\frac{1}{2}$ वर्ग मीटर क्षमता के कम नहीं होगा ।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में घास-फूस या गोबर इस स्थिति में या इस भांति नहीं रखेगा जिससे पेयजल दूषित होने की सम्भावना हो । यदि गोबर या घास-फूस कृषि के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है तो इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी चिनना आवश्यक चबूतरा, अधिमान्यता, सीमेंट कंक्रीट का ढेर या उपयुक्त आकार का गढ़ा बनायेगा जो वास्तविक रूप में जिसका प्रयोग घास-फूस, खाद तैयार करने के लिए घास-फूस डालने के लिए किया जाएगा । अधिमान, गोशाला और निवास स्थान से यह 40 मीटर की दूरी पर होना चाहिए ।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी परिसर को दिन में दो बार, प्रातः 9 बजे से पूर्व और सायं 4 बजे से पूर्व साफ कराने और सप्ताह में एक बार धोने का प्रबन्ध कराएगा । सारा कूड़ा-कर्कट, गोबर, टट्टी माल आदि उक्त शर्त के अनुसार उपबन्धित पात्रों में डाला जाएगा जिनको दिन में दो बार साफ किया जायेगा या जहां नगर निगम के कर्मचारियों की सेवा का इसके लिए उपयोग न किया जा सके तो कूड़ा-कर्कट को जलाने, पैक करने या दबाने की व्यवस्था की जायेगी ।

(च) यदि गोशाला या अस्तबल के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला परिसर किसी अलग-थलग स्थान पर स्थित हो और यदि निगम स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो तो वह कूड़ा-कर्कट, टट्टी आदि के निपटाने के लिए निर्दहिक उपलब्ध करायेगा । यह निर्दहिक स्वास्थ्य अधिकारी के अनुमोदित प्रकार की होगी ।

(छ) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर की भीतर की दीवारों को वर्ष में दो बार और यदि निगम स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित है तो इस से अधिक बार चूने से पोताई करवायेगा ।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी इस निमित्त नगर निगम द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को, अनुज्ञप्त परिसर और उसमें रखे पशुओं के निरीक्षण के लिए युक्ति-युक्त समय में प्रत्येक उचित सुविधा उपलब्ध करवायेगा ।

(झ) अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्त परिसर पर रखे पशुओं में किसी संक्रामक रोग के फैलने का बोध हो तो वह इसकी सूचना तुरन्त निगम स्वास्थ्य अधिकारी को देगा । जब तक स्वास्थ्य अधिकारी से कोई आदेश न मिले तब तक प्रभावित पशुओं को अलग रखा जायेगा ।

(ञ) यदि अनुज्ञप्त परिसर में दुधारू पशु रखे हैं तो अनुज्ञप्तिधारी इन पशुओं को सप्ताह में कम से कम एक बार ठीक ढंग से नहलाने का प्रबन्ध करेगा ।

(ट) अनुज्ञप्तिधारी युक्ति-युक्त अवधि में गोशाला या अस्तबल के लिये प्रयोग में लाए गए परिसर का निगम स्वास्थ्य अधिकारी की अपेक्षा के अनुसार उपांतरण, परिवर्तन और मुरम्मत करवायेगा ।

5. अनुज्ञप्त परिसरों की शर्तें.—किसी परिसर को गोशाला या अस्तबल के रूप में प्रयोग लाने के

लिए अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी यदि उक्त परिसर निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप न हो कि :-

(क) मानवीय निवास के प्रयोग में लाए जाने वाले कमरे से परिसर कम से कम 10 मीटर की दूरी पर स्थित है ;

(ख) उक्त परिसर में पानी के नल का कनैक्शन सीधा निगम की जल सप्लाई से जुड़ा है ;

(ग) परिसर के किसी भी भाग की ऊंचाई फर्श से दीवार प्लेट तक (आकमित) 3 मीटर से कम नहीं है ;

(घ) परिसर का फर्श, खुली जगह या गली की सतह से जिस ओर वह खुलता है कम से कम 1/2 मीटर ऊपर है जिसमें कुछ अप्रवेश्य सामग्री लगी है जो कम से कम 11.50 सैं0 मी0 मोटी है और इसकी ढाल जिस ओर पशुओं के मुंह हो उसके विपरीत है और ढलान का स्तर 1:30 के अनुपात से कम नहीं है ;

(ङ) परिसर का जल (निकास) पक्के सीमेंट से बनाया गया है और उक्त प्रयोजन के लिए बनाये गये गड्ढों से जुड़ा है और निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिए निदेशों के अनुसार निर्मित और व्यवस्थित है।

(च) परिसर मक्खी, धूप, हवा कक्ष सहित रोशनीदार और हवादार हैं ।

(छ) परिसर से कोई द्वार नहीं है जिससे सीधी हवा को किसी रसोई घर या मानवीय निवास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले स्थान को जाने की सम्भावना है ;

(ज) पशुओं को नहलाने और दिन में बांधने के लिये पर्याप्त उपयुक्त पानी के निकास वाले स्थान की व्यवस्था है जो इसका क्षेत्र फर्श क्षेत्र के सातवें भाग से कम नहीं है ।

6. परिसर में रखे जाने वाले पशुओं की संख्या.-- निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रत्यक अनुज्ञप्ति में पशुओं की संख्या उनका विवरण जो कि परिसर में रखे जा सकते हैं, विनिर्दिष्ट करेंगे । विनिर्दिष्ट संख्या ऐसी होगी कि प्रत्येक पशु के लिये सुरक्षित स्थान 3.25 मीटर लम्बाई और 2.50 मीटर की चौड़ाई से कम नहीं होगा और ऐसा स्थान नांद या किसी नियन्त्रण या ढाल निकास को छोड़कर है ।

7. जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तयों की संख्या.--किसी परिसर के लिये केवल एक अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी चाहे उक्त परिसर पर एक से अधिक पशु रखे हुए हैं ।

स्पष्टीकरण.-- उप-विधि 5(क) और (ख) में दर्शित से भिन्न किसी भवन या बिमा जो उप-विधियों के प्रवृत होने की तारीख को पहले ही अनुज्ञप्त है, का प्रयोग जारी रहेगा बशर्ते कि निगम का समाधान हो जाता है कि निकास और रोशनदान पर्याप्त है ।

8. शास्ति.--(क) कोई भी व्यक्ति जो अपनी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो अनुज्ञप्ति निलम्बित या प्रतिसंहृत की जा सकेगी ।

(ख) जो भी व्यक्ति इन उप-विधियों का उल्लंघन करेगा वह मैजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर जुर्माने से दंडनीय होगा जो 2,000 रुपए तक का हो सकेगा और निरन्तर उल्लंघन करने की दशा में प्रथम उल्लंघन से जब वह जारी रहता है 50 रुपए प्रतिदिन जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

9. निरसन और व्यावृति.-- पंजाब सरकार की तारीख 10 अगस्त, 1940 की अधिसूचना सं0 2927-सी0-40 के अधीन प्रकाशित उपविधियां एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं परन्तु ऐसी निरसित उप-विधियों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन उप-विधियों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

हस्ताक्षरित/
सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department notification No. LSG (A)-18/83, dated 3-4-86 is published under Article 348 (3) of the Constitution of India for general information of the public*].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd April, 1986

No. LSG- (A)-18/83.—The following Bye-Laws made by the Municipal Corporation, Shimla in exercise of the powers conferred by section 339 read with clause (H) of sub-section (I) of section 395 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1979 (Act No. 9 of 1980) having been approved by the Governor, Himachal Pradesh as required under section 397 of the aforesaid Act are hereby published for general information and shall come into force within the area of the Municipal Corporation, Shimla from the date of publication of this notification in the Himachal Pradesh Rajpatra:—

SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION STABLES AND COW HOUSES BYE-LAWS, 1985

1. *Short title & commencement.*—(1) These bye-laws may be called the Shimla Municipal Corporation Stables and Cow Houses Bye-Laws, 1985.

(2) These shall come into force atonce after thirty days from the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Definitions.*—In these bye-laws unless & until there is any thing repugnent in the subject or context,—

(*i*) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1979,
(*ii*) "Cow house" shall mean any place where oxen (for hire) or milk cattle are kept, and
(*iii*) "Stable" means any place where horses, ponies or mules are kept.

3. *Use of Premises.*—No person shall use or permit to be used any premises or part of any premises as a stable or a cow house unless he has obtained a license for such use from the Municipal Corporation. The Health Officer of the Corporation shall be the licensing authority.

4. *Conditions for License.*—License for the use of any premises or part of any premises as a stable or cow house shall be issued on an application to the owner or occupier of such premises. subject to following conditions:—

(*a*) The licensee shall not keep or permit to be kept in licensed premises at any time any number of animals in excess of the number prescribed in his licence or of a description other than that specified in his licence.
(*b*) The licensee shall not permit any person to cook in the licensed premises or to use them for human habitation; provided that a certain number of attendants, to be specified in the license may be permitted to sleep on the licensed premises, to prevent accidents to the animals.
(*c*) The licensee shall provide in some convenient places a receptacle or receptacles for dung, litter etc. Such receptacles shall be of such form and of such material as the Health Officer of the Corporation may direct and shall be of a capacity of not less that 1/2 sq. metres for each animal kept on the premises.
(*d*) The licensee shall not keep on the licenced premises any litter or dung in such a situation or manner as to pollute or likely to pollute any drinking water. Where litter or dung is required for agricultural purposes, a smooth impervious platform preferably of cement concrete or a pit of suitable size shall be built at least 40 metres away from the stable or cow house, or from any human habitation on which or in which the litter may be stacked preparatory to its being used as a manure.

(*e*) The licensee shall cause the licensed premises to be cleaned twice daily, before 9 a.m. and before 4 p.m. and to be washed down once every week. All litter, dung, rubbish etc. must be removed to the receptacles provided in accordance with condition (c) above which should be cleaned twice daily or should be disposed of by burning, packing or burrying where the services of Municipal staff can not be availed of;

(*f*) The licensee shall if the premises to be used as a cowshed or stable are in an isolated place and if so required by the Health Officer of the Corporation provide incinerator for the disposal of litter, rubbish etc. of a type approved by the Health Officer of the Corporation.

(*g*) The licensee shall cause all the interior walls of the licensed premises to be lime-washed at least twice yearly and more often if so required by the Health Officer of the Corporation.

(*h*) The licensee shall give every facility to any officer appointed by the Municipal Corporation in this behalf to inspect the licensed premises and the animals kept therein at any reasonable time.

(*i*) The licensee shall inform the Health Officer of the Corporation immediately if it comes to his knowledge, of any out break of any infectious disease among the animals kept on the licensed premises and shall segregate the animals affected pending the orders of the Health Officer of the Corporation.

(*j*) In case the animals kept on licensed premises are milch cattle, the licensee shall cause such animals to be properly washed at least once a week.

(*k*) The licensee shall carry out within a reasonable period any repairs, alterations, modifications or any such work in connection within premises used as cow-house or stable, as may be required to be done by the Health Officer of the Corporation.

5. *Conditions for Licensing Premises.*—No licence for the use of premises as cow-houses or stable shall be issued unless such premises conform to the following conditions:—

(*a*) that the premises are situate at a minimum distance of 10 metres away from any room used for human habitation;

(*b*) that the premises are fitted with a water tap connected directly with Municipal water supply;

(*c*) that the height of the premises is in no part less than 3 metres measured from the floor to the wall plates;

(*d*) that the floor of the premises is at least 1/2 metre above the level of the open space or street on to which they open, is paved with some impervious material at least 11.50 cm. thick and is sloped away from the heads of the animals to be stabled with a gradient of not less than one in thirty;

(*e*) that the premises are adequately drained by a pucca cemented and properly sloping drain into a soakage pit set apart for the purpose and constructed and maintained according to directions given by the Health Officer of the Corporation;

(*f*) that the premises are adequately lighted and ventilated with fly proof ventilaters and are provided with self closing wire gauge doors and windows;

(*g*) that there is no opening from the premises likely to permit direct ventilation therefrom into any cooking place or places used for human habitation; and

(*h*) that there is provided an adequately drained area equal to not less than one-seventh of the floor-area of the premises on which the cattle may be washed or tothered during the day.

6. *Number of Animals to be Kept in a Premises.*—The Health Officer of the Corporation shall in every licence specify the description and prescribe the number of animals which may be kept in the licensed premises. The number prescribed shall be such that there shall be reserved for each animal a space of not less than 3.25 metres in length and 2.50 metres in breadth, such space being exclusive of any manager or any central or side drain.

7. *Number of Licences to be issued.*—Only one licence shall be granted in respect of any premises notwithstanding that such premises may be occupied by more than one animal.

Explanation.—Any building of smaller dimensions than those indicated in bye-laws 5 (a) and (b) above, and which is already licensed on the date on which these bye-laws come into force may continue to be used provided the Corporation is satisfied that the drainage and ventilation are adequate.

8. *Penalty.*—(*a*) Any licensee who commits a breach of any of the conditions of his licence shall be liable to being suspended or revoked.

(*b*) Any person who commits a breach of these bye-laws shall, on conviction by a Magistrate, be punishable with fine which may extend to rupees two thousand, and if the breach is a continuing one, with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first breach during which the same continues.

9. *Repeal and Savings.*—Bye-laws published with Punjab Government notification No. 2927-C-40/33235, dated 10th August, 1940 are hereby repealed:

Provided that anything done or any action taken under the provisions of the Bye-Laws so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Bye-Laws.

By order,
Sd/-
Secretary.

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 12th December*, 1985

No. EXN. B(1)-8/82.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, and in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Excise and Taxation Commissioner (Legal) (Class-I Gazetted) in the Excise and Taxation Department, Himachal Pradesh as per Annexure-I.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Assistant Excise and Taxation Commissioner (Legal) Recruitment and Promotion Rules, 1985 for the post of Assistant Excise and Taxation Commissioner (Legal) Class-I Gazetted.

(2) These rules shall come into force from the date of issue of this notification.

2. Rules.—The number of posts, classification, pay scale, qualifications and method of recruitment for the post of Assistant Excise and Taxation Commissioner (Legal) in the Excise and Taxation Department, Himachal Pradesh shall be specified in the Annexure-I.

ANNEXURE I

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT EXCISE AND TAXATION COMMISSIONER (LEGAL) IN THE DEPARTMENT OF EXCISE AND TAXATION, HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT

1. Name of the post .. Assistant Excise and Taxation Commissioner (Legal).

2.	Number of posts ..	One
3.	Scale of pay ..	Rs. 1200-1850
4.	Classification ..	Class-I (Gazetted)
5.	Whether selection post or non-selection post. ..	Selection
6.	Age for direct recruits ..	As prescribed for direct recruitment to the H.P.A.S. from time to time.
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	*Essential:* (*i*) A professional Degree in Law of a recognised University; and (*ii*) Five year's experience in Legal/Court work. *Desirable:* Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Age: *No* Educational qualifications: *Yes.*
9.	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled by various methods.	100% by promotion, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer grades from which promotion, deputation/transfer to be made.	(*i*) By promotion from amongst Excise and Taxation Officers with at least 5 years regular service as such. (*ii*) By deputation of District Attorney having at least 3 years regular service as such.
12.	If a D.P.C. exists, what is its composition.	D.P.C. is to be presided over by the Chairman, H.P.S.C., or a Member thereof to be nominated by him.
13.	Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14.	Relaxation clause	Where the Government is of the opinion that it is neccssary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post.

FOOT-NOTES

1. A candidate for appointment to any service or post must be,—
   (*a*) a citizen of India, or
   (*b*) a subject of Nepal, or
   (*c*) a subject of Bhutan, or
   (*d*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
   (*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, The United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India/State Government.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India/Government of Himachal Pradesh.

2. Upper age-limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in the ervice of the Government.

3. Upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Tribes candidates and other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the H.P. Government.

4. Age-limit for direct recruits will be reckoned from the last date fixed for receipt of application by the Commission.

5. Age and experience for direct recruits relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

6. Provisions of columns 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under column 2 are increased or decreased.

7. Selection for appointment to these posts in the case of direct recruitment, shall be made on the basis of *viva-voce* test, if the Commission so consider necessary or expedient by a written test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission or practical test.

8. In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *adhoc* one) in the feeder post all persons senior to him in the respective category shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion/confirmation shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the relevant recruitment and promotion rules, for the post whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion/confirmation on account of the requirement prescribed in the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion/confirmation.

9. The employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servant before absorption in public sector corporation/autonomous bodies

at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed on the initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies.

10. The appointments to this service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

11. *Departmental examination.*—(*a*) Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1976 within the probation period or within two years from the notification of these rules whichever is latter failing which he shall not be eligible to:—

(*a*) cross the Efficiency Bar next due;
(*b*) confirmation in the service; and
(*c*) promotion to the next higher post:

Provided that if a member becomes otherwise eligible for promotion, within the period mentioned above, he shall be considered for promotion and if otherwise found fit, shall be promoted provisionally subject to his passing the departmental examination. He may be reverted if he fails to pass the same:

Provided further that an officer who has qualified the departmental examination in whole or in part prescribed under any other rules before the notification of these rules shall not be required to qualify the whole or in part of the examination as the case may be:

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the 1st March, 1976 shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules.

(*b*) An officer on promotion to a higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(*c*) The Government may in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission grant in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing exemption in accordance with the departmental examination rules to any class or category of persons from the departmental examination in whole or in part.

S. S. SIDHU,
Secretary.

भाषा एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 8 मई, 1986

संख्या भाषा-ग(17)-2 86.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, गेयटी थियेटर परियोजना मौनिटीरिंग समिति

गठन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त समिति के लिए सदस्य मनोनीत किए जाते हैं :—

1. सचिव (भाषा एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
2. सचिव (वित्त), हि० प्र० सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
3. आयुक्त (पर्यटन), हि० प्र० सरकार	सदस्य
4. आयुक्त, नगर निगम शिमला	सदस्य
5. उपायुक्त, शिमला	सदस्य
6. स्टेट टाउन प्लानर, हि० प्र०	सदस्य
7. श्री रत्नजीत सिंह, कन्वीनर, दी इन्डीयन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एन्ड कलचरल हैरिटेज, शिमला ।	सदस्य
8. सचिव, ए० डी० सी० क्लब, शिमला	सदस्य
9. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हि० प्र०, शिमला	सदस्य
10. पृथ्वी थियेटर बम्बई के प्रतिनिधि	सदस्य
11. निदेशक, भाषा एवं संस्कृति, हि० प्र०, शिमला	सचिव-सदस्य।

2. उक्त समिति गेयटी थियेटर, शिमला के जीर्णोद्धार तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करेगी ।

3. उपरोक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिकी भत्ता जैसा कि परिशिष्ट "अ" पर निर्दिष्ट है, देय होगा ।

4. वित्त विभाग की स्वीकृति उनके द०सं० 985-फिन (सी)बी (15) 11-84, दिनांक 24-4-86 द्वारा प्राप्त कर ली गई है ।

आदेशानुसार,
महाराज कृष्ण काव,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

परिशिष्ट "अ"

T.A. and D.A:

The T.A. and D.A. to the non-official members will be paid in the following manner:—

1. Travelling Allowance:

(*i*) *Journey by Rail.*—They will be treated at par with Government servants of the first grade and will be entitled to actual rail fare of the class of the accommodation actually used, but not exceeding the fare to which Government servants of the first grade are normally entitled *i.e.* accommodation of the higher class, by whatever name, it may be called provided on the railway by which the journey is performed.

(*ii*) *Journey by Road.*—They will be entitled to actual fare for travelling by single seat in a bus, and if the journey is performed by motor cycle/scooter mileage allowance at 50 paise per km in plain areas and 65 paise per km. in the hill areas and if the journey is performed by engaging own car/taxi the member will be entitled to mileage allowance @ Rs. 2/- per km. in hilly areas and Rs. 1.65 per km in plain areas.

2. In addition to the actual fare or milage as per item (*i*) and (*ii*) above, a member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence starting with departure from the and ending with arrival at that place, at the same rate and subject to the same terms and conditions as apply to Grade-I Officers of the State Government.

3. Daily Allowance:

Non-official members will be entitled to drRw daily allowance for each day of the meeting at the highest rate as admissible to a Government servant of the first grade for the respective locality.

In addition to daily allowance for the day (s) of the meeting, a member shall also be entitled to daily allowance for halt on tour at out station in connection with the affairs of the Committee as under:—

(*a*) If the absence from headquarter does not exceed six hours .. Nil.
(*b*) If the absence from headquarters exceeds six hours but does not exceed twelve hours .. 70%
(*c*) If the absence from headquarters exceeds twelve hours .. Full.

Daily allowance will be subject to the usual conditions laid down in Supplementary Rules, 1973 as amended from time to time.

4. Conveyance Allowanee:

A non-official member, resident at place where the meeting of the committee is held will not be entitled to travelling and daily allowance on the scale indicated above but will be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to a maximum of Rs. 10/- per day. Before the claim is actually paid, the Controlling Officer should verify the claim and satisfy himself, after obtaining such details as may he considered necessary, that the actual expenditure was not less than the amount claimed. In case he is not satisfied with the details, he may, at his discretion, limit the conveyance allowance to road mileage.

If such member uses his own car, he will be granted mileage allowance at the rates admissible to officials of the first grade subject to a maximum of Rs. 10/- per day.

The travelling and dialy allowance will be admissible to a member on production of a certificate by him to the effect that he has not drawn any travelling or daily allowance for the same journey and halts from any other Government sources.

The non-official members will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meeting of the Committee from and to the place of their permanent residence to be named in advance. If any member performs journey from a place other than the place of his permanent residence to attend a meeting of the Committee or return to place other than the place of his permanent residence after the termination of the meeting, travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance actually travelled of the distance between the place of permanent and the vanue of the meeting whichever is less.

The provision of rules 4.17 and 6.1 of the Himachal Pradesh Treasury Rules relating to over payments made to Government servants will apply mutatis mutandis in the case of over payment made on account of Travelling Allowance to non-official members.

The Director, Language and Culture, Himachal Pradesh, Shimla will be Controlling Officer in respect of countersigning of the Travelling Allowance bills of the non-official members and T.A. Bills shall also be prepared in his office.

OFFICIAL MEMBERS:

The offi ial members shall be entitled to the T.A. and D.A. according to the rules governing them.

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी

अधिसूचना

(नियम 45 देखिए)

मण्डी, 12 मई, 1986

सं0 4-मण्डी (इलैक)-21/85.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 4-मण्डी (इलैक)-11/85, दिनांक 30 सितम्बर, 1985 के अन्तर्गत विकास खण्ड सराज की ग्राम सभा 16-थाची से निर्वाचित प्रधान श्री देवी राम, ग्राम वरना, डाकघर थाची का नाम अधिसूचित किया गया है।

चूंकि अब हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 186 के अन्तर्गत उपरोक्त श्री देवी राम निर्वाचित प्रधान का निर्वाचन 2-5-1986 को अवैध घोषित किया जा चुका है और उनके स्थान पर श्री हरी राम सुपुत्र श्री चेत राम, ग्राम चोहड़ी, डाकघर थाची को ग्राम सभा थाची, विकास खण्ड सराज को प्रधान पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है।

अत : अब, मैं, राजवन्त सन्धू, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 45 में प्राप्त हैं, एतद्द्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए विकास खण्ड सराज की ग्राम सभा 16-थाची से निर्वाचित प्रधान श्री हरी राम सुपुत्र श्री चेत राम, गांव चोहड़ी, डाकघर थाची, को अधिसूचित करती हूं।

राजवन्त सन्धू,
उपायुक्त, मण्डी।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 7 मई, 1986

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0(5) 63/83.—क्योंकि श्री पुन्नु राम प्रधान, ग्राम पंचायत गागला, विकास खण्ड मैहला को जिलाधीश चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या 10(12)/73-3390, दिनांक 10 जुलाई, 1985 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत धोखा धड़ी के मामले में निलम्बित किया गया था ;

और इन आरोपों की जांच एस0 एच0 ओ0 चम्बा से करवाई गई । जांच रिपोर्ट में प्रतक्षतः आरोप सही सिद्ध हुए किन्तु उस द्वारा धोखा धड़ी से दिलाई गई ऋण राशियां वापस की गई हैं, इस प्रकार उस पर कोई कानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है।

क्योंकि अब उक्त प्रधान पंचायत के किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत श्री पुन्नु राम, भूतपूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत गागला, विकास खण्ड मैहला के विरुद्ध चले मामले को समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-2, 7 मई, 1986

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)21/79.—क्योंकि श्री सिधु राम, प्रधान ग्राम पंचायत धर्मपुर के विरुद्ध सरकार ने सम संख्यक कार्यालय आदेश, दिनांक 11-6-85 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त किया था, बाद में सरकार ने संयुक्त निदेशक पंचायती राज जो नए सिरे से जांच के आदेश दिए, जिन्होंने 31-3-86 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

और क्योंकि संयुक्त निदेशक पंचायती राज की रिपोर्ट को जांचने के बाद उक्त प्रधान के विरुद्ध लगे आरोप स्पष्ट रूप से सिद्ध तो नहीं हुए, परन्तु प्रधान को धन राशि के लेन देन में अवश्य लापरवाह पाया गया ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(4) के अन्तर्गत प्राप्त है एक तो जिलाधीश मण्डी के आदेश संख्या पी0सी0एम0-233-8(1)/53-271-276 दिनांक 15-1-86 को समाप्त करने का तथा दूसरे श्री सिधु राम को भविष्य में ग्राम पंचायत के कार्य संचालन में सावधानी बरतने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

हस्ताक्षरित/-
उप-सचिव ।

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 20 मई, 1986/30 वैशाख, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

मत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 13 मार्च, 1986

संख्या मत्स्य-क(3)-1/82.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग में सहायक निदेशक मत्स्य वर्ग-II (राजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम जो इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ०टी०-43-245/50(ई), दिनांक 1 अक्तूबर, 1963 द्वारा अधिसूचित किए गए और समय-समय पर संशोधित किए गए थे, को निष्प्रभावित करते हुए इस अधिसूचना में संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार सहायक निदेशक मत्स्य वर्ग द्वितीय (राजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियम सहर्ष बनाते हैं, अर्थात् :—

775-राजपत्र/86-20-5-86—1,390. मूल्य : 20 पैसे ।